The number of experts required at each plant are determined on a year to year basis. The tenure of individual experts are determined by the Soviet Organisations. Their present terms and conditions include entitlement to:

Transfer Grants.

Air passage for the specialist and his family.

Leave on full pay at the rate of one day for every 11 days, if a Specialist works in India.

Free medical attendance and treatment for the Specialist and his family.

Free transport to the site of work and back; and
Insurance.

सरकारी क्षेत्र के घाटे में कमी

1354. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के घाटे को कम करने के लिए उनके उत्पादों की कीमतें समय-समय पर बढ़ाई जाती हैं जिससे अन्ततः अन्य वस्तुओं की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उद्योग घाटे मे चल रहे हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन वस्तुओं की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की गई ; और

(ग) क्या इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई उपाय किये गये हैं और यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह अनुमान है कि माननीय सदस्य का आशय महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र जैसे इस्पात, कोयला आदि के बारे में नियंत्रित मूल्यों मूल्य वृद्धि से है, जिसके लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। अतः इनके लिये सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य-वृद्धि मुख्यत. काम मे आने वाली सामग्री की बढ़ी हुई लागत की प्रतिपूर्ति करना है, न कि सरकारी क्षेत्र के उद्योगों मे घाटे को कम करना ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त "क" के उत्तर को देखते हुये (ख) और (ग) के प्रश्न ही पैदा नही होते । किन्तु, 1983-84 में जिन उद्यमों ने घाटा उठाया है, उनके नाम लोक उद्यम सर्वेक्षण के खंड-1 में पृष्ठ 61 से 63 पर उपलब्ध हैं जिसे 15 मार्च, 1985 को राज्य सभा-पटल पर रखा गया था ।

इसी प्रकार, 31 मार्च, 1984 को समाप्त तीन वर्ष के दौरान काम में आने वाली आधारभूत सामग्री जैसे इस्पात, कोयला आदि में हुई मूल्य-वृद्धि का विवरण लोक उद्यम सर्वेक्षण 1983-84, 1982-83 और 1981-82 के खंड-1 में "सरकारी उद्यमों में मूल्य-निर्धारण नीति संबंधी" अध्याय में उपलब्ध है ।

"क्रिमिनल बैंकिंग" शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादकीय

1355. श्री **जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1985 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित "क्रिमिनल बैंकिंग" शीर्षक के अधीन प्रकाशित संपादकीय की ओर दिलाया गया है ,

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यों मे अनियमितताओं के लिये अध्यक्ष और प्रबंधक को दोषी पाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।